पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या - 14444/2021

=====

दिलीप कुमार पुत्र - राम प्रयोजन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट-किशनपुर मधुबन, थाना-तुर्की, जिला-
मुजफ्फरपुर, बिहार।

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छापरा।
4. पुलिस अधीक्षक, सिवान।
5. जांच अधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिवान।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

विभागीय कार्यवाही - याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट दी गई और न ही द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिया गया - परिणामस्वरूप उसे अपना बचाव करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का उचित अवसर देने से इनकार कर दिया गया।

हेल्ड - परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है।

सजा के आदेश तीन काले निशान, वेतन वृद्धि को दो साल तक रोकने के बराबर - रद्द - जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेज दिया गया।

भरोसा किया - भारत संघ बनाम मोहम्म रमजान खान, (1991)1 एससीसी 588।

प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल हैदराबाद बनाम बी करुणाकर और या (1993)4 एससीसी 737।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या - 14444/2021

=====

दिलीप कुमार पुत्र - राम प्रयोजन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट-किशनपुर मधुबन, थाना-तुर्की,
जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छापरा।
4. पुलिस अधीक्षक, सिवान।
5. जांच अधिकारी-सह-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सिवान।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए : -

श्री पुष्कर नारायण शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता।

सुश्री दीक्षा सिंह, अधिवक्ता

श्री राघवेंद्र कुमार, अधिवक्ता

श्री अमित आनंद, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए:- मोहम्मद एन. एच. खान, एससी-1

मोहम्मद फजल करीम, एससी-1 के ए.सी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

ओरल जजमेंट

दिनांक: 19-10-2023.

1. वर्तमान रिट याचिका पुलिस अधीक्षक, सीवान द्वारा पारित दिनांक 31.08.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिस द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता को दो साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने के बराबर तीन काले निशान की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा द्वारा पारित 19.06.2021 दिनांकित अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी है, जैसा कि पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा जारी ज्ञापन तिथि 05.07.2021 के माध्यम से सूचित किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 11.02.2009 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद वह संतोषजनक रूप से काम कर रहा था और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। जब वह गुथानी पुलिस स्टेशन, जिला सिवान के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात थे, एक रामभरोसा राय और कुछ अन्य व्यक्तियों ने महानिरीक्षक (उत्पाद शुल्क और निषेध) बिहार, पटना में शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने चावल से लदे एक वाहन को हिरासत में लिया था और साथ ही शराब के 32 डिब्बे भी लिए थे और 1.25 लाख रुपये की राशि लेकर उक्त वाहन को छोड़ दिया था। इसके बाद, जांच की गई और पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा याचिकाकर्ता को एक ज्ञापन जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया था और फिर एक विभागीय जांच की गई थी, जिसके बाद जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2019 और 23.08.2019 प्रस्तुत की थी, जिसमें सभी आरोपों को साबित पाया गया था। इसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यानी पुलिस अधीक्षक सिवान ने याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान किए बिना या कोई दूसरा कारण बताएँ नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता को सजा सुनाई है, दिनांक 31.08.2019 के विवादित आदेश के अनुसार, जिसे सजा सुनाई गयी है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अपील के द्वारा चुनौती दी गई थी, हालाँकि, उसे भी खारिज कर दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को न तो जांच रिपोर्ट की एक प्रति दी गई है और न ही याचिकाकर्ता को सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा कोई दूसरा कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया गया है, इसके परिणामस्वरूप न केवल याचिकाकर्ता को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उचित अवसर से वंचित किया गया है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है, इसलिए पूरी जांच कार्यवाही जिसका समापन दिनांक 31.08.2019 के दंड के विवादित आदेश को पारित करने में होता है और साथ ही अपीलीय आदेश भी कानून की नजरों में दूषित होते हैं, इस प्रकार खारिज किए जाने योग्य हैं।

4. इस मोड़ पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला बिना किसी सबूत का मामला है और शिकायतकर्ता और अन्य लोगों से जांच के दौरान गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है।

5. इसके विपरीत, हालांकि प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका का विरोध किया है, हालांकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि न तो याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की गई थी और न ही याचिकाकर्ता को कोई दूसरा कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था, इसलिए मामला जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से अनुशासनिक प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उन सामग्रियों का अध्ययन किया है जिनसे इस न्यायालय ने पाया है कि न तो याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही याचिकाकर्ता को कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उचित अवसर से वंचित कर दिया गया है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की पूरी विभागीय कार्यवाही, कानून की नजर में अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध है। इस संबंध में भारत संघ बनाम मोहम्मद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए। **भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान, (1991) 1 एस. सी. सी. 588** में के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय और साथ ही **प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल हैदराबाद बनाम के बी. करुणाकर और अन्य** ने (1993) 4 एस. सी. सी. 737 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गया संविधान पीठ का निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, मैं दिनांक 31.08.2019 के दंडादेश के साथ-साथ दिनांक 05.07.2021 में निहित अपीलीय आदेश को भी निरस्त करना और मामले को जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद के चरण से नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेजने को उपयुक्त और उचित मानता हूँ।

8. रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सोनल/-

खंडन (डिस्क्रेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।